जज एम जेयपॉल ।

मंजित सिंह, -पुटिशनर

बनाम

हरियानांद राज्य के राज्य

1990 का CWP नंबर 6552

22 नवंबर, 2010

हेल्ड, कि याचिकाकर्ता को एक अवसर दिए बिना याचिकाकर्ता के खिलाफ आयोजित की गई पूरी जांच के रूप में जांच अधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों को पूरी तरह से विचलित कर दिया गया है। जांच अधिकारी ने इस पर भरोसा करने के लिए कुछ सामग्री एकत्र की है और इस पर भरोसा किया गया था और याचिकाकर्ता को आरोप का दोषी पाया गया था। अनुशासनात्मक प्राधिकरण नेत्रहीन रूप से जांच अधिकारी की खोज से नहीं जा सकता। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को तौला जाने के बाद, वह केवल अच्छे और पर्याप्त कारणों के लिए जुर्माना लगाने वाला है। इसलिए, जांच अधिकारी द्वारा दी गई खोज के आधार पर पाठ्यक्रम के अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश अच्छे और शानदार कारणों को प्रतिबिंबित करेगा, जो उसके दिमाग में तौला गया था कि यह निर्णय देने के लिए कि उसके खिलाफ आरोप का दोषी पाया गया था। लेकिन, दुर्भाग्य से, अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को गुप्त पाया जाता है और यह अच्छे और शानदार कारण को प्रतिबिंबित नहीं करता है जो उसके द्वारा पारित अंतिम आदेश का हिस्सा होना चाहिए। इस आधार पर, अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश कानूनी जांच नहीं करता है।

(पैरा १३ और १४)

इसके अलावा, कि उत्तरदाताओं ने निलंबन की अवधि के दौरान पहले से ही

भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते से अधिक में भुगतान को रोकने के बारे में याचिकाकर्ता को एक अवसर देने के लिए एक अलग आदेश पारित करने में विफल रहे हैं। इसलिए, दंड का दूसरा अंग जो पंजाब सिविल सर्विसेज (सजा और अपील) के नियमों के नियम 4 के तहत चिंतन नहीं किया गया है, 1952 में अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा आदेश में अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है। याचिकाकर्ता को किसी भी अवसर की पुष्टि किए बिना निलंबन की अवधि के दौरान पहले से ही भुगतान किया गया भत्ता कानून में खराब है। चुनौती के तहत आदेश को याचिकाकर्ता को पर्याप्त अवसर दिए बिना और अस्पष्ट में नियमों के खिलाफ भी मनमाने ढंग से अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है। इसलिए, लगाए गए आदेश को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

(पैरा 17 और 18)

याचिकाकर्ता के लिए गोपी चंद, अधिवक्ता।

प्रतिवादी राज्य की ओर से सुखविंदर सिंह नारा, वरिष्ठ डीएजी, हरियाणा

जज एम जेयपॉल

2010 के सीएम नंबर 15203

सुना।

आवेदन की अनुमति है। उत्तरदाताओं की ओर से लिखित बयान नंबर 1 से 3 रिकॉर्ड पर लिया गया है। आवेदन का निस्तारण किया गया है।

सी -डब्ल्यू.पी. 1990 का नंबर 6552

(1) अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सजा से पीड़ित रुपये की राशि की वसूली का निर्देशन। रु। की दर से 30 समान किस्तों में 12,000। 400 प्रति माह और

निलंबन की अवधि के लिए याचिकाकर्ता की मजदूरी को भी प्रतिबंधित करते हुए, याचिकाकर्ता ने सीधे वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

(२) याचिकाकर्ता हरियाणा रोडवेज, अंबाला में एक ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था, जो कि उत्तरदाताओं के नंबर २ और ३ द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित होने वाले पहले प्रतिवादी का एक उपक्रम है।

(३) याचिकाकर्ता के रोजगार के दौरान, एक दुर्घटना 23 नवंबर, 1986 को भूतोली के पास हुई। याचिकाकर्ता को निम्नानुसार चार्ज किया गया था:-

"आप श्री मंजत सिंह चालक नंबर 5 23 नवंबर को वाहन संख्या 2369 के साथ ड्यूटी पर थे। 1986 को जगधरी-अंबाला मार्ग पर। आप वाहन को तेज गति से लापरवाही से और लापरवाही से चला रहे थे। जब आपका वाहन एक जगह भंबोली के पास पहुंचा, एक ट्रैक्टर-ट्रॉली आपके वाहन से आगे जा रहा था। आपने ट्रॉली के पीछे अपने वाहन को मारा, जिसके कारण वाहन दाईं ओर एक केकर के पेड़ के खिलाफ धराशायी हो गया, जबकि ट्रॉली को कछुए को बदल दिया गया, जिससे उस पर बैठे व्यक्तियों को चोट लगी। जिस पर रु। 12,320--43 पीएस की धुन पर खर्च किया गया था।

इस तरह से आप अपने वाहन को दहलाकर और लापरवाही से एक उच्च गति से चलाकर उस दुर्घटना का कारण बना, जिसके लिए सरकार। एक वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। यह ड्यूटी के निर्वहन में आपकी लापरवाही और अनुशासनहीन के कारण था "।

(४) आरोप का पदार्थ याचिकाकर्ता के खिलाफ दो प्रमुख आरोपों का खुलासा करेगा; पहला यह है कि वह तेज गति से वाहन चलाने में दाने और लापरवाही कर रहा था; और दूसरा यह है कि उन्होंने पहले प्रतिवादी के वाहन को नुकसान पहुंचाया और इस तरह पहले प्रतिवादी को रु। वाहन की मरम्मत के लिए 12,320-43।

(५) हरियाणा रोडवेज से जुड़े इंस्पेक्टर की जांच PW1 के रूप में की गई और एक अधिकारी जो ड्यूटी की जाँच कर रहा था, उसे जांच अधिकारी के समक्ष PW2 के रूप में

जांचा गया। PW1 और PW2 के साक्ष्य की पृष्ठभूमि में उत्पादित सामग्री के माध्यम से जाने वाले जांच अधिकारी ने यह पता लगाया कि याचिकाकर्ता ने वाहन को एक उच्च गति से दाने और लापरवाह तरीके से निकाल दिया और दुर्घटना का कारण बना और जिसके परिणामस्वरूप पहला उत्तरदाता ने रु। 12,320-43।

(६) अनुशासनात्मक प्राधिकरण जांच अधिकारी की खोज के माध्यम से चला गया और याचिकाकर्ता को अंतिम अवसर देने के बाद, याचिकाकर्ता को दोषी पाया और याचिकाकर्ता को उपर्युक्त सजा दी

(7) याचिकाकर्ता के लिए पेश होने वाले सीखा वकील निम्नानुसार होगा:-

याचिकाकर्ता को सौंपा गया चार्ज दोषपूर्ण था क्योंकि नुकसान का विवरण और उत्तरदाताओं द्वारा खर्च किए गए व्यय को विशेष रूप से नहीं दिखाया गया था। जांच के दौरान जिन दस्तावेजों का उत्पादन नहीं किया गया था, उन्हें याचिकाकर्ता के पीछे के पीछे जांच अधिकारी द्वारा भरोसा किया गया था। अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश एक बोलने का आदेश नहीं है। यह पूछताछ अधिकारी के समक्ष किसी भी सबूत की अनुपस्थिति में याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने का मामला है। उत्तरदाताओं द्वारा न तो दाने और लापरवाह ड्राइविंग और न ही नुकसान का सामना करना पड़ा और उत्तरदाताओं द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष स्थापित किया गया था। निलंबन अवधि के दौरान याचिकाकर्ता को उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए निर्वाह भत्ते के लिए वेतन को प्रतिबंधित करने की सजा कानूनी जांच के रूप में नहीं है क्योंकि अलग -अलग जांच की जानी चाहिए।

(8) उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित होने वाले वरिष्ठ उप अधिवक्ता जनरल इस प्रकार प्रस्तुत करेंगे: ----

याचिकाकर्ता ने क़ानून के तहत उपलब्ध अपील के वैकल्पिक उपाय को समाप्त नहीं करने के लिए चुना। PWI और PW2 के सबूत यह दिखाने के लिए जाएंगे कि याचिकाकर्ता वाहन को चलाने में लापरवाही कर रहा था और जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई। हर्जाना का विवरण और उत्तरदाताओं द्वारा खर्च किए गए खर्च को याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए

गए चार्ज में दिखाया जाना चाहिए। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पूरी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही आदेश पारित किया। निलंबन की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के वेतन को प्रतिबंधित करने वाले एक आदेश को पारित करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण शक्तियों के भीतर अच्छी तरह से है, जब याचिकाकर्ता के खिलाफ साबित हुए आरोपों के लिए सजा का एक आदेश लगाया जाता है।

(९) आरोप में केवल आरोपों का सारांश होगा ताकि यह समझने के लिए कि वास्तव में उसके खिलाफ क्या आरोप लगाया गया है, उसे यह समझने में सक्षम बनाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अपराधी को आरोप के एक अवलोकन पर समझना चाहिए कि उसके खिलाफ वास्तव में क्या आरोप लगाया गया था कि उसके खिलाफ अपने बचाव को स्थापित करने के लिए आरोप लगाया गया था। अग्रणी साक्ष्य के उद्देश्य के लिए आवश्यक सामग्री को एक अपराधी के खिलाफ फंसाए गए आरोप में भीड़ नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, मामले के साक्ष्य भाग को एक अपराधी के खिलाफ फंसाए गए चार्ज में पेश नहीं किया जाना चाहिए।

(१०) याचिकाकर्ता के खिलाफ फंसाए गए आरोप के सावधानीपूर्वक अपराध पर, यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता को स्पष्ट रूप से ध्यान दिया गया है कि वह वाहन को तेज गति से चलाने में दाने और लापरवाही कर रहा था और दुर्घटना का कारण बना। दूसरे, यह भी उनके लिए स्पष्ट किया गया है कि उत्तरदाताओं को रुपये का खर्च करना पड़ा। 12.320-43 उस वाहन को उबारने के लिए जो याचिकाकर्ता के दाने और लापरवाह ड्राइविंग के कारण एक दुर्घटना के साथ मिला। चार्ज के ये दो अंग क्रम में पाए जाते हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया सबमिशन कि आरोप दोषपूर्ण पाया जाता है, वह मुझे अपील नहीं करता है।

(११) आरोप पढ़ेगा कि उत्तरदाताओं को रु। 12,320-43 उस वाहन की मरम्मत के लिए जो दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। सभी निष्पक्षता में, उत्तरदाताओं को कार्यशाला अधिकारी की जांच करनी चाहिए थी, जिन्होंने वास्तव में क्षति का आकलन किया

था और क्षतिग्रस्त वाहन की मरम्मत के लिए प्रतिवादी द्वारा किए गए व्यय के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों का भी उत्पादन करना चाहिए था। जांच रिपोर्ट में पढ़ा जाएगा कि नुकसान का आकलन कार्यशाला अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। व्यय विवरण जो पूछताछ अधिकारी के समक्ष उत्पादन नहीं किया गया था या याचिकाकर्ता को खुद का बचाव करने के लिए दिखाया गया था, दुर्भाग्य से जांच अधिकारी द्वारा भरोसा किया गया था। पूछताछ अधिकारी को सामग्री को अपराधी से इकट्ठा करने के लिए नहीं माना जाता है और एक लिंडिंग देने के लिए उसी पर भरोसा करता है कि अपराधी को दोषी पाया गया था। एक अपराधी अपने बचाव को आगे बढ़ाने के लिए एक अवसर का हकदार है, जैसा कि जांच अधिकारी द्वारा भरोसा की गई सामग्रियों के लिए।

(१२) इस संदर्भ में, असम राज्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए निम्नलिखित टिप्पणियों और एक अन्य बनाम महेंद्र कुमार दास और अन्य, (1): (1):- (1):- (1) को संदर्भित करना प्रासंगिक है।

"22 ..... लेकिन, हमें यह बताना होगा कि यह एक पूछताछ अधिकारी के लिए अत्यधिक अनुचित है कि किसी भी सामग्री को बाहरी स्रोतों से एकत्र करने का प्रयास करने के लिए एक जांच के संचालन के दौरान और उस जानकारी को नहीं, इसलिए एकत्र किया गया, जो कि एकत्र किया गया, जो कि अपराधी के लिए उपलब्ध है अधिकारी और आगे पूछताछ की कार्यवाही में उसी का उपयोग करते हैं। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां एक बहुत ही चालाक और आश्चर्यजनक जांच अधिकारी अपराधी अधिकारी की पीठ के पीछे बाहरी जानकारी एकत्र कर सकते हैं और, एकत्र की गई जानकारी के किसी भी स्पष्ट संदर्भ के बिना, संबंधित अधिकारी के खिलाफ उसके द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में प्रभावित हो सकते हैं। Il'it यह स्थापित है कि जांच के दौरान अपराधी अधिकारी के पीछे की सामग्री एकत्र की गई है और इस तरह की सामग्री को जांच अधिकारी द्वारा भरोसा किया गया है, इसके बिना इसका खुलासा नहीं किया गया है, यह कहा जा सकता है कि जांच में कहा जा सकता है कार्यवाही को विचित्र किया जाता है। ”

(13) उपरोक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को लागू करते, मुझे लगता है कि जांच अधिकारी द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, याचिकाकर्ता को अवसर दिए बिना याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई पूरी जांच पूरी तरह से दूषित है।

(१४) जैसा कि मेरे द्वारा पहले ही बताया गया था कि जांच अधिकारी ने इस पर भरोसा करने वाले नाजुक के पीछे कुछ सामग्री एकत्र की है और याचिकाकर्ता को आरोप का दोषी पाया है। अनुशासनात्मक प्राधिकरण नेत्रहीन रूप से जांच अधिकारी की खोज से नहीं जा सकता। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को तौला जाने के बाद, वह केवल अच्छे और पर्याप्त कारणों के लिए जुर्माना लगाने वाला है। इसलिए, जांच अधिकारी द्वारा दी गई खोज के आधार पर पाठ्यक्रम के अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश उन अच्छे और पर्याप्त कारणों को प्रतिबिंबित करेगा, जो उनके दिमाग में तौला गया था कि यह निर्णय देने के लिए कि उनके खिलाफ आरोप का दोषी पाया गया था। लेकिन, दुर्भाग्य से, अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को गुप्त पाया जाता है और यह अच्छे और पर्याप्त कारण को प्रतिबिंबित नहीं करता है जो उसके द्वारा पारित अंतिम आदेश का हिस्सा होना चाहिए। इस आधार पर, अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश कानूनी जांच नहीं करता है।

(१५) जैसा कि मेरे द्वारा पहले से ही बताया गया है कि याचिकाकर्ता/अपराधी के खिलाफ चार्ज में दो अंग हैं। सभी निष्पक्षता में, विभाग को दुर्घटना के लिए कम से कम एक चश्मदीद गवाहों की जांच करनी चाहिए थी ताकि यह स्थापित किया जा सके कि याचिकाकर्ता अपने ड्राइविंग में दाने और लापरवाही कर रहा था। इसी तरह, विभाग को आधिकारिक संबंधित को नुकसान और संबंधित अधिकारी की जांच करनी चाहिए, जिन्होंने वाहन को उबारने के लिए खर्च किया। लेकिन, इस मामले में हरियाणा रोडवेज के पीडब्ल्यूआई इंस्पेक्टर और पीडब्लू 2 के अधिकारी जो अकेले ड्यूटी की जाँच कर रहे थे, उन्हें विभाग के किनारे पर जांचा गया था। बेशक, दोनों दुर्घटना के दृश्य के बाद ही दुर्घटना के दृश्य पर पहुंच गए। तो,

यह स्पष्ट है कि दोनों दुर्घटना के लिए चश्मदीद गवाह नहीं थे। कम से कम कहने के लिए, वे याचिकाकर्ता के कथित दाने और लापरवाही से ड्राइविंग के बारे में बोलने के लिए सभी सक्षम नहीं हैं या वाहन को होने वाले नुकसान के कारण विभाग द्वारा वास्तविक नुकसान का सामना करना पड़ा। पीडब्ल्यूआई और पीडब्लू 2 के हार्स सबूतों को जांच अधिकारी द्वारा गंभीर रूप से ध्यान में रखा गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि याचिकाकर्ता आरोप का दोषी था।

(१६) अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने लागू आदेश को पारित करते हुए निलंबन अवधि के लिए वेतन को उस राशि के लिए प्रतिबंधित कर दिया, जिसे याचिकाकर्ता ने पहले से ही निर्वाह भत्ते की ओर आकर्षित किया था। स्थापित आरोपों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण केवल पंजाब सिविल सर्विसेज (सजा और अपील) के नियम, 1952 के नियम 4 के तहत चिंतन किए गए जुर्माना लगा सकता है। सरकार के लिए, निलंबन, सेवा से हटाना और सेवा से बर्खास्तगी को केवल पूर्वोक्त नियमों के पूर्वोक्त प्रावधानों के अनुसार अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा दंड के रूप में लगाया जा सकता है। निलंबन अवधि की अवधि के दौरान पहले से ही निर्वाह भत्ते की ओर खींची गई राशि के लिए अपराधी के वेतन को प्रतिबंधित करना उपरोक्त नियमों के तहत चिंतन किए गए दंडों में से एक नहीं है। श्री बी.डी. गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा (2), ने पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स (Vol.-I, PART-1) के नियम 7.3 के तहत सरकार द्वारा पारित प्रासंगिक आदेश का उल्लेख किया है, जो नियम 7 के तहत किसी भी आदेश को पारित करने से पहले (3) (3) निलंबन की अवधि के दौरान पहले से ही प्राप्त निर्वाह भत्ता से अधिक के भुगतान को रोककर, वह अपने प्रतिनिधित्व को करने के लिए अपराधी को एक अवसर देगा।

(17) उत्तरदाताओं ने निलंबन की अवधि के दौरान पहले से ही भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते से अधिक में भुगतान को रोकने के बारे में याचिकाकर्ता को एक अवसर देते हुए एक अलग आदेश पारित करने में विफल रहे हैं। इसलिए, पंजाब सिविल सर्विसेज (सजा और अपील) के नियमों के नियम 4 के तहत पैनाल्टी का दूसरा अंग जो चिंतन नहीं किया गया है, 1952 में अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा आदेश में अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा

पारित किया गया है। याचिकाकर्ता को किसी भी अवसर की पुष्टि किए बिना निलंबन की अवधि के दौरान पहले से ही भुगतान किया गया भत्ता कानून में खराब है।

(१ 8) उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, मुझे लगता है कि चुनौती के तहत आदेश अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा मनमाने ढंग से याचिकाकर्ता को पर्याप्त अवसर दिए बिना और अस्पष्ट में नियमों के खिलाफ भी पारित किया गया है। इसलिए, लगाए गए आदेश को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

(१९) उत्तरदाताओं के लिए सीखा वरिष्ठ उप अधिवक्ता जनरल द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुत करने के लिए आ रहा है कि अपील के वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका दायर की गई है। मुझे लगता है कि 20 साल पहले ही उस तिथि से आ चुके हैं जब याचिकाकर्ता ने इस अदालत से उपाय की मांग की है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि उन्होंने अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की, लेकिन इसका निपटान नहीं किया गया था। लेकिन उत्तरदाताओं ने लगभग 20 वर्षों की चूक के बाद ही रिट याचिका का जवाब दायर किया है, जिसमें अदालत को सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपील पसंद नहीं की गई थी।

(२०) उस समय जब इस मामले को इस न्यायालय द्वारा भर्ती किया गया था, उत्तरदाताओं द्वारा वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के रूप में कोई प्रारंभिक आपत्ति नहीं उठाई गई थी, जो याचिकाकर्ता द्वारा रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान करके इस अदालत से संपर्क करने से पहले समाप्त नहीं किया गया था। मुझे लगता है कि यह एक अतिरिक्त साधारण मामला है, जहां याचिकाकर्ता को एक उपाय की तलाश करने के लिए लगभग 20 वर्षों के चूक के बाद अपीलीय मंच से पहले जाने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब लगाए गए आदेश को टिकाऊ नहीं पाया जाता है, जैसा कि प्राकृतिक के सिद्धांतों के रूप में इस मामले में न्याय का पालन नहीं किया गया था।

(२१) बेशक, याचिकाकर्ता के लिए पेश किए गए वकील ने सुखदिप सिंह मान बनाम भारत

के संघ में इस न्यायालय के एक फैसले का उल्लेख किया, (३) घर लाने के लिए इस बात को लाने के लिए कि एक बार याचिका को डिवीजन द्वारा योग्यता के लिए स्वीकार किया जाता है अदालत की बेंच, मुख्य याचिका मेरिट पर तय की जाएगी।

(२२) ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक आपत्ति उस विशेष मामले में उठाई गई थी, जो इस आधार पर रिट याचिका की रखरखाव के रूप में थी कि अपील का एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था, लेकिन उस प्रारंभिक आपत्ति को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि डिवीजन बेंच ने चुना योग्यता पर मामले के अंतिम स्थगन के उद्देश्य के लिए रिट याचिका को स्वीकार करें। लेकिन हाथ में मामले के तथ्य और परिस्थितियां पूरी तरह से अलग हैं। वर्तमान मामले में कोई प्रारंभिक आपत्ति नहीं जताई गई थी, क्योंकि इस आधार पर रिट याचिका की रखरखाव थी कि एक वैकल्पिक उपाय था याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध है। इसलिए, पूर्वोक्त अनुपात इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होगा। किसी भी दर पर, मुझे लगता है कि 20 लंबे वर्षों की चूक के बाद अपनी शिकायत का निवारण करने के उद्देश्य से अपीलीय प्राधिकरण के सामने जाने के लिए याचिकाकर्ता को निर्देशित करना अन्यायपूर्ण होगा।

(२३) उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, मुझे लगता है कि लागू आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं पाया गया है। इसलिए, चुनौती के तहत लगाए गए आदेश को खारिज कर दिया गया है और वर्तमान रिट याचिका की अनुमति है। जैसा कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेश को समाप्त कर दिया जाता है, याचिकाकर्ता को निलंबन की अवधि के दौरान शेष राशि प्राप्त करने का हकदार है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई हो, तो याचिकाकर्ता से तय किए गए आदेश के अनुसार, उसे वापस कर दिया जाएगा। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश का विभाग द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही पर कोई असर नहीं होगा।

**अस्वीकरण** : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

प। रिंदर सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

जींद, हरियाणा